लोकहितम् मम करणीयम्

INDIAN INSTITUTE OF DEMOCRATIC LEADERSHIP

An initiative of Rambhau Mhalgi Prabodhini

Newsletter July 2023

Post Graduate Programme in Leadership, Politics and Governance

- 8 students took admission to the 7th batch of IIDL's PGP
- The admission process for the 7th batch is going on and to register

Click here to Apply Now

Admissions Open for 2023-24 Batch

Alumni/ Student Updates

Placements of Batch VI Students

Varahe Analytics selected the following students during campus placements

Anay Mulik

Anisha Chavan

Mihir Iyer

Maitreyee Bapat

Sharath Chandra Chendi

Abhijith Nair

IIDL batch VI students who joined as interns at the office of Vinod Tawde, National General Secretary, BJP

Devendra Kumar Bajpai

Satyvardhan Das Bairagi

Udit Mohan Pathak

Other Student Updates

Arshia Rashid
joined the Political Anchor on New India Junction at Bluekraft Digital Organisation

Sushil Kumar D
joined Office of K Annamalai, State President, Tamil Nadu, BJP

Nayan Dwivedi
started a new blog
www.nayannotes.substack.com
Read More

RMP
RESEARCH CENTRE

- Students Proposal has been submitted for Title Registration at Mumbai University of three students - Steven Loboo, Aakansha Wani, and Devendra Pai

UDAAN FELLOWSHIP

- Online monthly meeting of the fellows was held on 30 June 2023 where the Research fellows presented their PPT and the political fellows gave information about their work.

Other IIDL Updates

Devendra Pai represented RMP- C20 at Together VCAN 's Social Sanchar Panel discussion organised with Savishkar on atmanirbharsuraksha: 'Electrical Safety is Non Negotiable ' held at the Royal Bombay on 15th July.

Devendra Pai spoke on Uniform Civil Code on July 10th at Narendra Modi Vichar Manch, Bhayandar. Highlighted why the need to have a Uniform Civil Code, disparities in civil laws esp with regards to property transfer rules, and complex legal issues arising out of multiple personal laws on civil issues.

A discussion on "The Role of Media in a Democracy and State of Press Freedom in the World" was organised with American journalist, Joel Simon along with IIDL selected teachers and alumni on July 6th. Discussed how journalists in the process of gaining eyeballs and TRPs have sensationalised news harming their own credibility.

IIDL in collaboration with the Prof Bal Apte Centre for Students and Youth movements, University of Mumbai organised the C20 Regional Roundtable on Delivering Democracy at the Mumbai University campus on July 04, 2023, in the presence of Dr. Prof Ravindra Kulkarni, Vice Chancellor of the University of Mumbai and Dr. Ajay Bhamare, Pro Vice-Chancellor, the University of Mumbai.

Media

राजनीतिक दलों के लिए बन गया है रणनीतिक हथियार

देवेंद्र पई
कोर्स डायरेक्टर, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप

आगामी चुनाव से ठीक पहले अविश्वास प्रस्ताव लाना कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा बन गया है। हालांकि विपक्ष का यह रवैया ठीक नहीं है। मात्र अपने राजनीतिक लाभ के लिए पूरी संसद ठप कर देना और बिना आधार के अविश्वास प्रस्ताव लाना, लोकतंत्र के व्यापक हित में नहीं है।

लोकसभा में मौजूदा केंद्र सरकार के विरुद्ध विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव आया है। संविधान में अविश्वास प्रस्ताव की कोई व्यवस्था नहीं है। लोकसभा की नियमावली में इसका प्रविधान किया गया है। आदर्श रूप में अविश्वास प्रस्ताव उस स्थिति में संतुलन बनाता है, जब किसी सरकार के पास सदन में पर्याप्त सदस्यों का समर्थन न रह जाए। गठबंधन सरकार की स्थिति में इसकी भूमिका बढ़ जाती है। पहली बार अगस्त, 1963 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया था। चीन से युद्ध के बाद आचार्य कृपलानी यह प्रस्ताव लाए थे। आचार्य कृपलानी जानते थे कि उनका प्रस्ताव गिर जाएगा, फिर भी वह प्रस्ताव लेकर आए। तभी ये यह परिपाटी भी बन गई। अब तक अविश्वास प्रस्ताव में मतदान से कोई सरकार नहीं गिरी है।

कुल मिलाकर अविश्वास प्रस्ताव राजनीति में एक रणनीतिक हथियार बनकर रह गया है। इसके कारणों में सरकार का प्रदर्शन और सदस्यों का समर्थन बमुश्किल ही देखने को मिलता है। लोकसभा चुनाव से एक या दो सत्र पहले अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से विपक्ष आगामी चुनाव का एजेंडा तय करना चाहता है। यह विपक्ष के लिए सरकार पर सवाल उठाने का माध्यम बनता है। मणिपुर की समस्या को कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव का एजेंडा बनाना चाहती है। कांग्रेस की ओर से इससे पहले 2018 और 2003 में भी अविश्वास प्रस्ताव आगामी चुनाव से सालभर के भीतर ही लाए गए थे। 2003 में जहां कांग्रेस एजेंडा सेट करने में सफल रही थी, वहीं 2018 में यह कदम उसे भारी पड़ा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे विपक्ष के खिलाफ ही प्रयोग कर लिया।

अगले आम चुनाव को नौ महीने से भी कम समय बचा है। ऐसा में लगता नहीं है कि मणिपुर के अलावा विपक्ष के हाथ में सरकार के खिलाफ कोई और मुद्दा लग पाएगा। दूसरी ओर, भाजपा समान नागरिक संहिता पर जन अभियान शुरू करने का प्रयास कर रही है। इस कदम ने विपक्षी एकता में दरार भी दिखा दी है। शिवसेना (उद्धव ठाकरे) और आम आदमी पार्टी इसे अपना समर्थन दे चुके हैं। अनुच्छेद 370 की तरह इस मुद्दे पर भी सबको साथ रखना कांग्रेस के लिए मुश्किल है। कांग्रेस जानती है कि राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद जनवरी में भव्य श्रीराममंदिर का अनावरण और फरवरी में बजट के रूप में भाजपा के तरकश में बहुत कुछ है। ऐसे में उसकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह से सरकार को घेरा जाए। फिलहाल अविश्वास प्रस्ताव लाकर कांग्रेस इस बात से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है कि वह सरकार के विरुद्ध जनता के समक्ष कोई मुद्दा रखने में विफल रही है।

एक और बात, कांग्रेस जानती है कि अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। इसके बावजूद 2003 और 2018 की तरह उसने चुनाव से पहले यह दांव चला है। इससे विपक्षी दलों की ओर से हाल ही में बने गठबंधन की भी परख हो जाएगी। फिलहाल इस गठबंधन में बनते ही दरारें दिखने लगी हैं। इस दांव से कांग्रेस को कितना फायदा होगा, यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव का यह राजनीतीकरण चिंताजनक है। इससे न केवल संसदीय कार्य बाधित होते हैं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। विपक्ष अपने राजनीतिक फायदे को राष्ट्र के हितों से ऊपर रख रहा है और संसद के कार्य को बाधित किए हुए है। संसद में बहस नहीं होने दी जा रही है और कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा को रोका जा रहा है, जिससे अंततः करदाताओं का ही नुकसान हो रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि राजनीतिक दल अविश्वास प्रस्ताव की इस प्रक्रिया का न्यायिक एवं जिम्मेदारीपूर्ण प्रयोग करें। उन्हें मात्र बाधा खड़ी करने के, ऐसी रचनात्मक बहस एवं चर्चा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे पूरे देश को लाभ हो।